भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 819

दिनांक 6 फरवरी 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

व्यापार समझौते और आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिरोधक्षमता

819 श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चल रही वार्ताओं की वर्तमान स्थिति और समझौते पर हस्ताक्षर करने की विशिष्ट समय सीमा क्या है;

(ख) भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) की स्थिति सहित प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ वर्तमान में चल रहे अन्य नए व्यापार समझौतों या वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा वैश्विक तनावों के कारण उत्पन्न समुद्री व्यवधानों और रसद संबंधी बाधाओं से भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपाय कर रही है; और

(घ) अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के दृष्टिगत आपूर्ति श्रृंखला स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं हेतु "आयात प्रतिस्थापन" कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (भारत-ईयू एफटीए) के संपन्न होने की संयुक्त रूप से घोषणा की। अनिवार्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ख): भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू), श्रीलंका के साथ व्यापार समझौतों पर वार्ता कर रही है और आसियान और दक्षिण कोरिया के साथ मौजूदा समझौतों की समीक्षा कर रही है। सरकार ने इज़राइल, मालदीव, फिलीपींस और खाड़ी सहयोग परिषद

(जीसीसी) के साथ व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए निबंधन एवं शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हाल ही में, सरकार ने दिनांक 24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) और दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भागीदार देशों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एक व्यापार समझौते की घोषणा की है। सरकार ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए वार्ता भी पूरी की है।

(ग) और (घ): सरकार संस्थागत समन्वय को मजबूत करके, सूचना-साझाकरण तंत्रों में सुधार करके, उद्योग जगत के साथ मिलकर तनाव के बिंदुओं की पहचान करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाकर भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत विविधतापूर्ण और सतत् आपूर्ति श्रृंखलाओं को सहयोग देने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिसमें इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीएफई) भी शामिल है।

भारत ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन स्तंभ के तहत नेतृत्वकारी भूमिका ग्रहण की है, जिस पर नवंबर 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और जो फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में, भारत क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिमों को कम करने के लिए कमजोरियों का आकलन करने, महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करने और सहयोगात्मक तंत्र विकसित करने के लिए भागीदार देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन अध्ययन समूह का गठन किया गया है, जो प्रमुख मंत्रालयों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमजोरियों का आकलन किया जा सके, जोखिम कम करने की कार्यनीतियों का प्रस्ताव दिया जा सके और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ प्रयासों को संरेखित किया जा सके।

***